Free Higher Secondary Education in Delhi

3161. Shri Yajna Datt Sharma:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Hardayal Devgun:
Shri Virendrakumar Shah:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the Delhi Metropolitan Council has decided to make education free upto Higher Secondary level;

(b) whether they have approached the Central Government for financial assistance for implementation of the scheme; and

(c) if so, the amount asked for and the reaction of the Central Government thereto?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) No such decision has yet been communicated to the Ministry of Education.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

गोपाल रेड्डी समिति का प्रतिवेदन

3162. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री रामावतार सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगर परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने केन्द्र पर यह आरोप लगाया है कि उसने दिल्ली की समस्या की उपेक्षा की है ;

(ख) क्या गोपाल रेड्डी समिति की सिफारिशों के क्रियान्वित न किये जाने के कारण यह उपेक्षा हुई है ;

(ग) यदि हां, तो गोपाल रेड्डी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली प्रशासन से इस आरोप के बारे में कोई औपचारिक निर्देश प्राप्त नहीं हुआ कि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली की समस्याओं की उपेक्षा की है ।

(ख) से (घ). दिल्ली में स्थानीय निकायों के साधनों तथा आवश्यकताओं के बारे में जांच के लिये नियुक्त जांच आयोग ने श्री बी० गोपाल रेड्डी की अध्यक्षता में दिल्ली नगर निगम के तथा नई दिल्ली नगर पालिका के सामान्य स्कन्ध के वित्तीय मामलों पर एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी । आयोग ने बाद में 7 मार्च, 1967 को हुई अपनी बैठक में अपनी सिफारिशों की पुनः जांच करने का निश्चय किया । सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Code of Discipline

3163. Shri K. P. Singh Deo: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Committee to enquire into the breach of code of discipline in industries has been set up by Government;

(b) whether it is also a fact that some cases are pending disposal since 1965; and

(c) if so, the action taken in this regard?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) The reference is perhaps to the tripartite Central Implementation and Evaluation Committee which was set up in 1958 to ensure implementation of the Code of Discipline in Industry.

(b) Very few cases of 1965 are pending for final disposal.

(c) Efforts are being made to get the pending cases settled.